

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 12/19

GCMS NO 2019/00018

श्रीमती पानो पत्नि कल्याण जाति माली निवासी तीन दरवाजा करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांत

बनाम



1. भंवर
2. मुरारी पिसरान किशोर
3. योगेश पुत्र शंकर
4. सरोज पत्नि भंवर जातियान आदिगौड निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
5. बाबूद्वीन पुत्र शकूर जाति मुसलमान निवासी इमलीवाला बाग करौली तहसील व जिला करौली

रेस्पोंड

(अपील विरुद्ध मु०नं० 84/05 निर्णय दिनांक 4.1.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला० श्री श्यामप्रकाश गर्ग

अभिभाषक रेस्पोंड श्री रामजीलाल अग्रवाल

दिनांक 28.02.2025

निर्णय

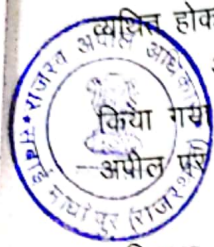
प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय दिनांक 4.1.19 न्यायालय उप जिला कलेक्टर, करौली पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे सायला/अपीलांत द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजीयात ख०न० 7660,7661,7685 लगायत 7870, 7872,7663 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 5 बीघा 7 विस्वा वाके कस्बा करौली सायला की खरीद शुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। जिसमे गैर सायलान का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। गैर सायलान सहजोर किस्म के व्यक्ति है। गैरसायलान न० 1 ता 3 व 5 हमारे खेत के पडोसी है और हमारी जमीन से इनकी जमीन की सीमा लगी हुई है। ताकत के बल पर हमारे खेतो मे घूस कर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। दिनांक 14.7.05 को समस्त गैरसायलान ताकत के बल पर जबरन बेदखल करने की धमकी दी है। गैरसायलान हमारी जमीन को अपने खेतो मे मिलाने पर उतारू है। इस कारण यदि गैर सायलान इस मकसद मे सफल हो गये तो सायला को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं हक हकूक सायला पर गहरा आघात होगा। इस कारण गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजीयात कुल रकबा 5 बीघा 7 विस्वा करौली मे सायला के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से




राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायला/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैर सायलान को सायला की उक्त भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करने एवं सायला को गैरसायलान की आराजीयात ख0न0 6669/9811, 7658, 7659, 7868/9753,7655 वाके कस्बा करौली के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करने अर्थात एक दूसरे की भूमि एक दूसरे को दखल नहीं करने का आदेश पारित किये जाने से



व्यक्ति होकर अपीलांट/सायला द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश कानून के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात अपीलांट के खाते व कब्जे की रही है। रेस्पों अपीलांट की जमीन को अपनी जमीन से मिलाने पर उतारू है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जो निर्णय होने तक जारी रही थी। रेस्पों ने अपीलांट के सीसम के पेड व कुआ तक को अपना बताने लग गये। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पाबन्द कर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। रेस्पों जबाब/काउन्टर क्लेम शुद्ध हस्त से नहीं आया है जबाब काउन्टर क्लेम में रेस्पों ने यह तक दर्ज नहीं किया है कि कौनसी जमीन पर मुझे पाबंद कराना चाहते हैं। काउन्टर क्लेम की दादरसी में कही भी यह दर्ज नहीं है। रेस्पों के खाते की जमीन में पाबन्द किया जावे बल्कि रेस्पों विवादित जमीन जो मुझ अपीलांट की है। उसमें मुझे पाबंद कराने की दादरसी चाही थी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। काउन्टर क्लेम सिर्फ उसी जायदाद या विवाद का चल सकता है जो दावे में दर्ज हो। प्रतिवादी यदि कोई अन्य दादरसी चाहता है तो उसे अलग से दावा करना चाहिए था। इस बात पर अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है। रेस्पों का काउन्टर क्लेम कब कहां व किस प्रकार विनाय दावा पैदा हुई और किस कारण से काउन्टर क्लेम की दादरसी लेना चाहता है। काउन्टर क्लेम में दर्ज नहीं होने पर भी रेस्पों का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर अदालत मातहत ने भूल की है। गैरसायल रेस्पों अपनी जमीन की आड में मेरी जमीन को अपनी बताने लग गये है। अब काउन्टर क्लेम स्वीकार होने पर गैरसायलान इस अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में मेरी जमीन में मदालखत कर मेरी जमीन को छीनने पर उतारू हो सकते हैं। इस तथ्य को अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है। अपीलांट का केस प्रथम दृष्टया मजबूत है। गैरसायल/रेस्पों ने काउन्टर क्लेम की आड में मुझ अपीलांट को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीयां को बड़ी तकलीफ होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी। सुविधा का संतुलन भी मेरे पक्ष में है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे आदेश दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पों ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट द्वारा केवल मात्र रेस्पों की जमीन में अनावश्यक व्यवधान


राजेश्वर अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डालने की नियत से पेश किया गया था। अपीलांट अपनी आराजीयात पर पूर्ण रूप से काबिज काशत है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की आराजीयात के बावत किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया है। उसके द्वारा केवल मात्र कपोल कल्पित बाते बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। रेस्पो0 की आराजीयात ख0न0 6669/9811, 7658, 7659, 7868/9753,7655 वाके कस्बा करौली में अनाधिकार रूप से बाधा उत्पन्न की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायला/अपीलांट को गैरसायलान/रेस्पो0 की आराजीयात में व्यवधान नहीं डालने एवं रेस्पो0/गैरसायलान को अपीलांट/सायला की आराजीयात में व्यवधान नहीं डालने हेतु विधि के अनुरूप ही पाबन्द किया गया है। अपीलांट द्वारा वाद कारण का जो उल्लेख किया गया है वह मनगढ़न्त है। रेस्पो0 द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी व विनाय दावा उत्पन्न नहीं किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट एवं रेस्पो0 की आराजीयात पास पास है। अपीलांट के कथन अनुसार रेस्पो0 अपीलांट की आराजीयात में बाधा उत्पन्न करता है तथा रेस्पो0 के कथन अनुसार अपीलांट रेस्पो0 की आराजीयात में बाधा उत्पन्न करता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो0 को एक दुसरे की आराजीयात में बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं निर्माण कार्य नहीं करे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वाहुलता उत्पन्न नहीं हो इस तथ्य को दृष्टिगत ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 84/05 में पारित निर्णय दिनांक 4.1.19 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.2.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
जिस्त अपील प्राधिकारी
रोजस्त अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर